आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार एकांश
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शनिवार 22.08.2026
समय 0720

मुख्य समाचार :–

- केंद्र सरकार ने कहा– देश में घरेलू मांग पूरी करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्योग जगत से उत्तराखंड में निवेश का आह्वान किया।
- नैनीताल में निर्मित रेशम कोया की राखियों की दुबई तक पहुंच, महिला स्वयं सहायता समूहों को मिला नया बाजार।
- और... अल्मोड़ा जिले में 16 से 23 सितंबर तक मां नंदादेवी का ऐतिहासिक मेला आयोजित किया जाएगा।

चीनी

केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वह स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। पिछले महीने की 20 तारीख को चीनी की कीमत 48 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो कल बढ़कर करीब 55 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।

मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। मंत्रालय के अनुसार, इथेनॉल के लिए चीनी का उपयोग वर्ष 2022–23 में करीब 12 प्रतिशत था, जो 2025–26 में घटकर करीब 9 प्रतिशत रह गया है। देश में इथेनॉल का करीब तीन–चौथाई हिस्सा अब अनाज, खासकर मक्का से तैयार होता है। मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमतों में मौजूदा बढ़ोतरी के पीछे कई कारण हैं। इनमें घरेलू उत्पादन का अनुमान से कम रहना, त्योहारी सीजन से पहले मांग बढ़ना, मौसम के कारण गन्ने की फसल को नुकसान, वैश्विक स्तर पर चीनी की कम उपलब्धता तथा कुछ वर्गों द्वारा जमाखोरी और सट्टेबाजी शामिल हैं।

इंडिया टुडे ग्रुप

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्योग जगत से उत्तराखण्ड की संभावनाओं को देखते हुए राज्य में निवेश करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड औद्योगिक विकास, स्टार्टअप, स्वरोजगार, डिजिटल अर्थव्यवस्था और बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से संतुलित विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नई दिल्ली में इंडिया टुडे ग्रुप के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

श्री धामी ने कहा कि औद्योगिक विकास का लाभ केवल मैदानी क्षेत्रों तक सीमित न रहे, इसके लिए पर्वतीय जिलों में भी औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पौड़ी, अल्मोड़ा और चमोली में औद्योगिक पार्क विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वहीं, 'एक जिला–दो उत्पाद' पहल के माध्यम से स्थानीय उत्पादों, छोटे उद्यमियों और पारंपरिक आर्थिक गतिविधियों को बाजार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली–देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, हवाई सेवाओं और बेहतर सड़क संपर्क से राज्य की कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। उन्होंने पंतनगर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को औद्योगिक और लॉजिस्टिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया।

श्री धामी ने कहा कि पर्यटन, स्वरोजगार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों के विस्तार से राज्य में रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा मिल रहा है।

राखियां

नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित रेशम विभाग कार्यालय में पंजीकृत महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा रेशम कोया से तैयार राखियां अब दुबई के बाजारों तक पहुंच रही हैं। रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए समूह से जुड़ी महिलाएं मांग के अनुरूप राखियों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए तेजी से उत्पादन कर रही हैं।

मां लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष रेखा रानी ने बताया कि वह पिछले छह महीने से समूह से जुड़कर रेशम आधारित उत्पाद तैयार कर रही हैं। उन्होंने बताया कि समूह अब तक करीब दो से तीन लाख रुपये का कारोबार कर चुका है।

मां नंदादेवी मेला

अल्मोड़ा जिले में 16 से 23 सितंबर तक मां नंदादेवी का ऐतिहासिक मेला आयोजित किया जाएगा। आठ दिवसीय मेले को लेकर मेला समिति ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मेला संयोजक तारा चंद्र जोशी ने बताया कि मेले में लोकगीत, लोकनृत्य सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी, जिनमें राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया कि समिति की ओर से विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारियां भी की जा रही हैं। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके माध्यम से स्थानीय प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराना भी है।

ग्राम्य गो सेवक योजना

रुद्रप्रयाग में पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं, पशुपालकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी आशीष रावत ने बताया कि महिला बकरी पालन योजना के तहत गरीब, निराश्रित, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को 35 हजार रुपये की लागत की यूनिट दी जा रही है। इसमें तीन बकरियां और एक बकरा शामिल है। गत वित्तीय वर्ष में जिले की 20 महिलाओं को इसका लाभ मिला। वहीं, गो पालन योजना में 21 अनुसूचित जाति की महिलाओं का चयन किया गया।

सामान्य वर्ग के लिए गो पालन योजना में एक गाय की यूनिट स्थापित करने के लिए 40 हजार रुपये दिए जाते हैं। इसमें 90 प्रतिशत राज्यांश और 10 प्रतिशत लाभार्थी का अंश होता है। बॉयलर पालन योजना के तहत बाड़ा तैयार करने में सहायता, चूजे और 60 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है। गत वर्ष 25 लाभार्थियों को इसका लाभ मिला।

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी ने बताया कि ग्राम्य गो सेवक योजना ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ रही है। इसके तहत पांच नंदियों के पालन–पोषण के लिए लाभार्थी को प्रतिमाह 12 हजार रुपये दिए जाते हैं।

और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर....

मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना पर अमर उजाला सीएम धामी के हवाले से लिखता है– देहरादून में जल्द बनेगा राज्य स्तरीय विपणन केंद्र।

1 अक्टूबर से नकद निकासी से जुडे नियम पर नवोदय टाइम्स का शीर्षक है– एसबीआई एटीएम से 4 से अधिक निकासी पर देने होंगे 15 रुपये

चमोली टेल रेस सुरंग हादसे पर दैनिक जागरण की सुर्खी है– विष्णुगाड सुरंग हादसे में मृत श्रमिकों के आश्रितों को 45–45 लाख मुआवजा।

मॉनसून की सक्रियता पर हिन्दुस्तान लिखता है– उत्तराखंड में अभी कुछ और दिन बारिश से राहत नहीं, चार जिलों में 23 को भारी बारिश की संभावना।

उच्चतम न्यायालय के हवाले से नवोदय टाइम्स लिखता है– एक साल अनुभव वाले वकील दे सकेंगे न्यायिक सेवा परीक्षा।